कार्यक्रम की नियमित मानीटरी की जा रही है ।

(ख) बिहार राज्य में जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अधीन स्थापित किये गए नए एककों की संख्या तथा 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान प्रदान किए गए रोजगार के अवसरों की संख्या निम्न प्रकार है :—

सूचक	1985-86	1986-87
1. स्थापित किए गए नए एककों की संख्या :		
(1) कारीगर	5091	5141
(2) लघु उद्योग	5428	4800
कुल :	10519	9941
2. प्रदान किए गए अतिरिक्त रोजगार के अवसरों की संख्या : (व्यक्तियों की संख्या)	56519	48755

(ग) जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम की समीक्षा तथा जांच के आधार पर इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यह कार्यक्रम बिहार के किसी भी जिले में असफल रहा है ।

वन/ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को एल०पी० जी० की आपूर्ति

3432. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह बताया था कि वन क्षेत्रों में ऊंचाइयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को गैस की आपूर्ति उन्हीं दरों पर की जाएगी जिन दरों पर इनकी आपूर्ति निकटवर्ती शहरों में उपभोक्ताओं को की जा रही है ; और

(ख) सरकार इस योजना के कार्यान्वयन के लिए तत्काल क्या-क्या प्रबन्ध कर रही है तथा मुंगेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को गैस की आपूर्ति के लिए क्या-क्या प्रबन्ध किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) बजट स्पीच में कहा गया है कि यह निर्णय किया गया है कि सभी पहाड़ी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को एल.पी.जी. सिलिण्डर उसी कीमत पर दिए जायेंगे जिस कीमत पर निकटतम मैदानी इलाकों में उपभोक्ताओं को दिए जाते हैं ।

(ख) उपर्युक्त स्कीम के क्रियान्वयन के लिए कदमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । तेल उद्योग मुंगेर जिले सहित पूरे देश के उन स्थानों को, जिनकी जनसंख्या 20,000 या इससे अधिक है (1981 की जनगणना के अनुसार) और जहां एल.पी.जी. के व्यवहार्य विपणन के लिए पर्याप्त, तत्व मौजूद हों, चरणबद्ध रूप से सामान्यतः हाथ में लेता है । उपर्युक्त के होते हुये ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में एल.पी.जी. सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Import of potassium iodate

3433. SHRIMATI ELA RAMESH BHATT: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that large quantities of potassium iodate are imported for iodisation of common salt in the country.

(b) whether potassium iodate cannot be manufactured in the country by public sector or other units; and

(c) whether shortage of imported potassium iodate is responsible for shortage of iodised salt?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNA-

CHALAM): (a) and (b) No, Sir. For manufacture of potassium iodate, iodine, which is not being manufactured in the country is imported in bulk. Small scale units produce potassium iodate in the country.

(c) No shortage of iodised salt has been reported from any part of the country. Against the target of 7 lakh tonnes of iodised salt fixed for the year 1986-87, the actual production was 7.73 lakh tonnes. The target for this financial year has been fixed at 12 lakh tonnes. Against this target, a production of 13.8 lakh tonnes has already been achieved till January, 1988.

Workshop on Pesticides

3434. SHRIMATI ELA RAMESH BHATT: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the UNIDO had organised a workshop on pesticides through the Hindustan Insecticides Limited recently and if so, what are the details thereof;

(b) whether the HIL had given the pride of place to some members of Pesticide Association of India, including multinationals belonging to it and Indian Explosives Limited; and

(c) whether the HIL had been approached by a natonal voluntary agency to attend some sessions as observer but permission was not given and if so, what were the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) Yes, Sir. A 5-week International Training Programme on quality control of Pesticides formulation was organised as a part of PEST programme sponsored by the World Bank, FAO, UNDP and UNIDO in New Delhi in October-November, 1987. Representatives from China, Korea, Indonesia, Thailand, India and Srilanka participated in the programme.

(b) Since the selection was made by the respective countries and finally by the World Bank, the question of HIL, who were the regional coordinator for the programme, having given pride of place to anyone does not arise. There were three participants from India, none of them from Indian Explosives Limited.

(c) As it was only a 'Training Programme' and not a 'Seminar', there was no question of allowing anybody as "observer". Since HIL was only a coordinator and not a sponsorer in this programme, the question of giving permission by them does not arise.

डाकतार विभाग की जोनल स्तर पर बैठकें

3435. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार मंत्रालय/संसद सदस्यों के साथ रेल मंत्रालय की भांति जोनल स्तर पर अपनी बैठक करने का विचार रखती है ; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुत थोड़े संसद सदस्य महाडाकपाल द्वारा बुलाई गई सर्किल स्तर की बैठकों, जिनमें राज्य को सर्किल माना जाता है, में इसलिए भाग नहीं लेते क्योंकि उन्हें सार्थक नहीं समझते ; और

(ग) क्या डाकतार विभाग ने देश में राज्य स्तर पर उपभोक्ता सलाहकार समितियां बनायी हैं, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो किस मंच पर उपभोक्ताओं के लिए सुविधाओं से संबंधित मामलों पर विचार किया जाता है ?